

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जून 2026 — ज्येष्ठ 20, शक 1948

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/36/2026-MRD.— यतः, पहचान साबित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने में लोगों को आसानी और निर्बाध रूप से सहायिकी (सब्सिडी), लाभ और सेवाएँ मिलती है; पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत समाप्त हो जाती है, प्रक्रिया आसान हो जाती है और पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलता है;

और यतः, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) (जो इसमें इसके पश्चात 'एजेंसी' के रूप में निर्दिष्ट है) जो छत्तीसगढ़ सरकार (जो इसमें इसके पश्चात राज्य सरकार के रूप में निर्दिष्ट है) खनिज साधन विभाग (जो इसमें इसके पश्चात, यथास्थिति, 'उक्त मंत्रालय' या 'उक्त विभाग' के रूप में निर्दिष्ट है) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, द्वारा "स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को टिन अयस्क के क्रय मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण" (जो इसमें इसके पश्चात 'उक्त योजना' के रूप में निर्दिष्ट है) का संचालन किया जाता है;

और यतः, "स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को देय टिन अयस्क का क्रय मूल्य" (जो इसमें इसके पश्चात "उक्त लाभ" के रूप में निर्दिष्ट है) उन "सहकारी समितियों के सदस्यों" को दिया जाता है, जिनमें मात्र स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही सदस्य हों और जो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के साथ पंजीकृत हों; जो CMDC के टिन क्रय केंद्र पर एकत्रित टिन अयस्क जमा करते हैं; और उपरोक्त व्यक्ति के पास छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र विस्तृत जानकारी और अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ [माईस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (क्र. 67 सन् 1957) की धारा 4 सुसंगत सूचनाओं के साथ देखें]; उक्त योजना और उससे संबंधित जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्देश के अंतर्गत धारण करते हैं (जो इसमें इसके पश्चात 'लाभार्थियों' के रूप में निर्दिष्ट है)

और यतः, उक्त योजना पर होने वाला व्यय, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधीन छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) द्वारा वहन किया जा रहा है;

और यतः, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) इच्छुक है कि राज्य सरकार, उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसे लाभार्थी का अभिप्रमाणन करवाए या आधार नंबर होने का प्रमाण दे या अगर किसी व्यक्ति को अभी तक आधार नंबर नहीं मिला है, तो वह नामांकन के लिए आवेदन करें;

अतएव, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों (सब्सिडी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016) (जो इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्वारा, आधार संख्या के प्रमाण के लिए निम्नलिखित निर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) उक्त योजना के तहत उक्त प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति को अधिप्रमाणन करवाना होगा या आधार नंबर होने का सबूत देना होगा।

(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे आधार नंबर नहीं दिया गया है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

परन्तु यदि वह व्यक्ति बालक/बालिका है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लाभार्थियों जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, उनका नामांकन किया जाए या वे उचित उपायों से अपने आधार संबंधी ब्यौरों को अद्यतन करे, जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय बैठाना, सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्र स्थापित करना या रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं नामांकन सुविधाएं प्रदान करवाना है :

परन्तु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार नंबर नहीं मिल जाता, तब तक वह उक्त लाभ को उठाने के लिए अपनी पहचान साबित करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज पेश कर सकता है, जिनके लिए वह हकदार है और जो पेश करने के समय वैध हैं या यदि उक्त छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) द्वारा ऐसे पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी को उन प्राधिकरण के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो उन्हें तैयार करने या बनाये रखने का काम करती है, तो वह ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दे सकता है, अर्थात्:—

18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका, जिसे आधार नंबर नहीं मिला है:

(अ) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई, लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की अभिस्वीकृति, जिसमें नामांकन ID (EID) शामिल हो; और

(ब) यह साबित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, दिये गये दस्तावेजों में से एक, अर्थात्:—

(एक) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (क्र. 18 सन् 1969) के तहत दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से लिया गया है;

(दो) भारतीय पासपोर्ट;

(तीन) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा, या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकसूची;

(चार) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे या “कानून से संघर्षरत” बालक/बालिका के मामले में, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान में रहते हैं, उस संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक (सुपरिटेण्डेंट), बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी द्वारा जारी किया गया, बच्चे की जन्म तिथि बताने वाला प्रमाण पत्र; या

(पाँच) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(क) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी, या नेपाल/भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा, अथवा वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(स) लाभार्थी की तस्वीर वाले निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, जिससे माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ उसका रिश्ता साबित हो, जैसे:—

- (एक) राशन कार्ड;
- (दो) राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या तहसीलदार के पद से निम्न रैंक का राजस्व अधिकारी न हो, द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;
- (तीन) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया मेडिकल या बीमा पहचान पत्र ;
- (चार) भारतीय पासपोर्ट;
- (पाँच) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकसूची;
- (छः) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक/बालिका, या कानून के साथ संघर्षरत बालक/बालिका के सम्बन्ध में, जो किशोर न्याय के बच्चों (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान में रहता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या
- (सात) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
 - (क) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक हैं, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड ;
 - (ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र;
 - (ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
 - (घ) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी, या नेपाल या भूटान के नागरिक नहीं है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा, या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या
- (आठ) जिस लाभार्थी का कोई विधिक संरक्षक है, उसके संबंध में, गोद लेने का आदेश या विधिक संरक्षक होने का प्रमाण देने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो गार्डियन्स एंड वार्ड्स एक्ट, 1890, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ़ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 (1999 का सं. 44) या राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016 (2016 का सं. 49) और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के तहत किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो; या
- (नौ) कोई अन्य दस्तावेज, जैसा कि उक्त खनिज साधन विभाग निर्दिष्ट कर सकता है।

जिन लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें अभी तक कोई आधार नंबर नहीं मिला है, उनके लिए :

- (अ) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई, लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की अभिस्वीकृति, जिसमें नामांकन ID(EID) हो; और
- (ब) लाभार्थी की फोटो वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जैसे :—
 - (एक) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
 - (दो) राशन कार्ड;

- (तीन) राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के पद से निम्न रैंक का राजस्व अधिकारी न हो, द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;
- (चार) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
- (पाँच) भारतीय पासपोर्ट;
- (छः) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा, या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकसूची;
- (सात) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज़;
- (आठ) दिव्यांगजनअधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी किया गया विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र;
- (नौ) भारत में जारी किया गया चालान अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस);
- (दस) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिका या विधि के साथ संघर्षरत बालक/बालिका के सम्बन्ध में, जिन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान में रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या
- (ग्यारह) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
- (क) यदि वह 'भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;
- (ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र;
- (ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (घ) वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी, या नेपाल/भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा, अथवा विदेशी पासपोर्ट (जो वर्तमान में वैध हो या जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी हो) के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा या
- (बारह) जिस लाभार्थी का कोई विधिक संरक्षक है, उसके संबंध में, गोद लेने का आदेश, या विधिक संरक्षक होने का सबूत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज़, जो गार्डियन्स एंड वार्ड्स एक्ट, 1890, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ़ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 या राईट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016, और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के तहत किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो; या
- (तेरह) कोई अन्य दस्तावेज़ जैसा कि उक्त खनिज साधन विभाग निर्दिष्ट कर सकता है।
- (4) इस संबंध में उक्त खनिज साधन विभाग द्वारा नामित अधिकारी, खंड (3) के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी सामग्री को साबित करने वाली जानकारी के संबंध में निम्नलिखित की जाँच करेगा,—
- (अ) myAadhaar पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर EID जमा करके नामांकन निवेदन (रिक्रेस्ट) की प्राप्ति की जाँच करें, ताकि यह पुष्टि हो सके कि EID वैध है और नामांकन निवेदन (रिक्रेस्ट) अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

- (ब) दूसरे दस्तावेज और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या प्राधिकरण से मदद ले सकते हैं और उनके साथ जानकारी बांट सकते हैं, जो ऐसे दस्तावेजों में मौजूद जानकारी को तैयार करने या बनाए रखने का काम करती है।
2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए मंत्रालय, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि लाभार्थियों को उक्त योजना के तहत आधार नंबर की आवश्यकता के बारे में जानकारी हो सके।
3. जहां किसी लाभार्थी की आधार नंबर का प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण के किसी भी तरीके (जैसे, चेहरे की इमेज, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन-आधारित प्रमाणीकरण) से बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता (क्वालिटी) जैसे किसी भी कारण से असफल हो जाता है, तो निम्नलिखित सुधार तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:—
- (अ) अगर बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण का कोई विशेष माध्यम सफल नहीं होती है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण का कोई दूसरा तरीका या वन-टाईम पिन (OTP) आधारित प्रमाणिकरण दिया जाएगा;
- (ब) ऐसे मामलों में, जहाँ बायोमेट्रिक-आधारित या OTP-आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं हैं, तो UIDAI के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का आधार सिक्वोर क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके आधार नंबर की वास्तविकता/यथार्थता स्थापित करने के बाद, बताई गई योजना के तहत लाभ इनमें से किसी भी आधार पर दिए जा सकते हैं।
- (एक) आधार कार्ड, आधार लेटर (यानी, आधार नंबर बनने पर आधार नंबर होल्डर को जारी किया गया लेटर) या ई-आधार (यानी, UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकने वाली या उसके mAadhaar ऐप से एक्सेस की जा सकने वाली पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी) वाला एक आधार सिक्वोर क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड, जिसकी वास्तविकता/यथार्थता आधार QR स्कैनर या mAadhaar ऐप का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन से की गई हो।
- (दो) आधार पेपरलेस ऑफलाइन e-KYC दस्तावेज (UIDAI) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकने वाला या उसके mAadhaar ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकने वाला, जिसकी वास्तविकता इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना लागू करने वाले अधिकरण (एजेंसी) द्वारा विकसित एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर UIDAI के हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट के ऑफलाइन सत्यापन से की गई हो, UIDAI की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार।
4. ऊपर अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी,—
- (अ) उक्त योजना के तहत किसी बालक/बालिका को लाभ देने से वंचित नहीं किया जाएगा—
- (एक) प्रमाणीकरण द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने के स्थिति में; या
- (दो) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहाँ उसे आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है; और
- (ब) उक्त योजना के तहत लाभ ऐसे बालक-बालिका को उसकी पहचान सत्यापन करके और पैराग्राफ 1 के खंड (3) के प्रावधान में बताई गई रीति से उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके रिश्ते को साबित करके दिया जाएगा; और
- (स) जहां खंड (ब) के तहत लाभ दिया जाता है, वहां उसका एक रिकार्ड रखा जाएगा, खनिज साधन विभाग द्वारा जिसका समय-समय पर समीक्षा और अंकेक्षण किया जाएगा।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक हकदार लोगों को इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम D-26011/04/2017-DBT, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 में बताए गए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का पालन करेगा (जो <https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध है)।

6. यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनायक शर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th June 2026

NOTIFICATION

No. RULE-801/36/2026-MRD.— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (CMDC) (hereinafter referred to as the 'agency') under the administrative purview of the Department of Mineral Resources (hereinafter referred to as the 'said Ministry' or the 'said Department', as the case may be) in the Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the State Government) is administering "Direct Benefit Transfer of purchase value of Tin Ore to local Scheduled Tribes" (hereinafter referred to as the 'said scheme'):

And whereas "Purchase value of Tin Ore payable to local Scheduled Tribes" (hereinafter referred to as the 'said benefit') is given to "the member of cooperative society in which only local Scheduled Tribes Persons are members and is registered with Chhattisgarh Mineral Development Corporation; who submit the collected Tin Ore at the Tin Purchasing Center of CMDC; and holds the identity card with full details and attested passport size photo issued by Chhattisgarh Mineral Development Corporation [refer to section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no 67 of 1957) along with relevant notifications]" (hereinafter referred to as 'the beneficiaries') under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is being incurred by Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited under the Government of Chhattisgarh State:

And whereas the said Chhattisgarh Mineral Development Corporation (CMDC) is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the 'said Act'), the Government of Chhattisgarh hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

- (3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Chhattisgarh Mineral Development Corporation (CMDC) shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Chhattisgarh Mineral Development Corporation (CMDC) for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned,-

- (A) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and
- (B) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:—
- (i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969(No 18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
 - (ii) Indian passport;
 - (iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (v) In respect of a foreign national,—
 - (a) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (b) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (c) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (d) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (C) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—
- (i) Ration card;
 - (ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (iv) Indian passport;
 - (v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (vii) In respect of a foreign national,—

- (a) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
- (b) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
- (c) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
- (d) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (No. 8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (No. 44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (ix) Any other document as the said Department of Mineral Resources may specify.

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (A) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and
- (B) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) Ration card;
 - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;
 - (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;
 - (ix) Driving licence issued in India;
 - (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

- (xi) In respect of a foreign national,—
 - (a) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (b) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (c) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (d) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or Competent Authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (No. 8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xi) Any other document as the said Department of Mineral Resources may specify:

(4) An officer designated by the said Department of Mineral Resources in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (A) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Enrolment ID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
 - (B) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
- (A) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
 - (B) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

- (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.
4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—
- (A) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—
- (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
- (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and
- (B) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
- (C) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department of Mineral Resources.
5. In order to ensure that bona fide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (CMDCL) shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).
6. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VINAYAK SHARMA, Deputy Secretary.